‘कौन बनेगा प्रधानमंत्री’ वाला प्रहसन

-मनोज कुमार झा

इस साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोक सभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच खलबली-सी मची है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, पर पिछले दो दशक में काफ़ी ताकतवर हो चुके क्षेत्रीय दल और क्षत्रप भी कुछ कम नहीं। राजनीतिक समीकरण बनाने-बिगाड़ने में इनकी भूमिका अहम् होगी।

बताया जाता है कि यह गठबंधन राजनीति का दौर है। कांग्रेस और भाजपा जैसे दल अगर अपने साथ क्षेत्रीय दलों को न जोड़ें तो हर्गिज सरकार बना पाने लायक मत नहीं जुटा सकते। टुकड़े-टुकड़े में देश को लूटने की कवायद ने तरह-तरह के क्षेत्रीय दलों को जन्म दिया। स्थानीय दबंग इन दलों में हावी होते चले गए। आज मुलायम, नितीश, रामविलास पासवान, लालू जैसे नेता इन्हीं क्षेत्रीय दलों के क्षत्रप हैं। इनमें कई का पराभव हो गया तो कई आज भी राज्य स्तर पर ही सही, लूट के अपने साम्राज्य को बनाये रखने में सफल साबित हो रहे हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो दिल्ली की गद्दी पाने का स्वप्न देख रहे हैं और इसके लिए हर तिकड़म करने को तैयार हैं।

ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू, ओमप्रकाश चौटाला, शरद पवार आदि भी ऐसे ही क्षत्रप हैं। इनमें से कई क्षत्रप राज्यों में ‘लूटतंत्र’ का सफल संचालन कर रहे हैं तो कुछ सत्ता से दूर फ़िर से उसे पाने की जुगत में लगे हैं।

देश के वामपंथी दल अलग ध्रुव हैं। हर पांच साल बाद आम चुनावों के मौके पर ये वामपंथी गैर भाजपा-गैर कांग्रेस विकल्प की बात करते हुए तीसरे मोर्चे के गठन का उपक्रम करने लगते हैं, जबकि अनेकों मौकों पर वामपंथियों ने काग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को चलवाने में प्रमुख सहयोगी की भूमिका निभाई है। परमाणु करार के मुद्दे पर इन्होंने संप्रग सरकार से समर्थन वापस लिया था, पर इनके हिलाए सरकार हिली नहीं और ये स्वयं राजनीति के अरण्य में भटकने को मजबूर हो गए।

अब चुनाव सिर पर देख, ये फिर तीसरा मोर्चा बनाने के लिये सक्रिय होते दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि इनकी ताकत लगातार घटती ही चली जा रही है। तीन दशक से ज्यादा समय तक ये पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कुंडली मारकर बैठे रहे। तृणमूल की ममता दीदी ने इन्हें भगाया और अब वो इनकी शैली में ही राजपाट चलाये जा रही है। जनता को तनिक भी राहत नहीं मिली।

इस बार तीसरा मोर्चा बनाने के लिये मुलायम सिंह यादव काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी उन्हें स्वयं प्रधानमंत्री बनने का अच्छा-खासा चांस दिख रहा है, पर उनके पुत्र अखिलेश के राज में यूपी में गुंडागर्दी की सारी सीमाएं टूटती नज़र आ रही हैं। मुज़फ़्फ़रनगर दो-दो बार दंगों की भीषण आग में झुलस चुका है। दंगा-पीड़ित महिलाओं के साथ रेप होना आम बात है। खास बात ये है कि अखिलेश ने डीएसपी मर्डर कांड में फंसे ‘कुंडा के गुंडा’ रघुराज प्रताप सिंह को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। मुलायम सिंह अब तक संकट की हर घड़ी में सोनिया-मनमोहन सरकार के रक्षक की भूमिका में नज़र आए हैं। मुलायम ख़ुद कहते रहे हैं कि कांग्रेस का साथ देना उनकी मजबूरी थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सोनिया सीबीआई से पकड़वा कर उन्हें जेल में डाल देती। सच कहा मुलायम ने। अगर ऐसा हो जाता तो इस देश में समाजवाद की स्थापना के महान लक्ष्य को कितना बड़ा धक्का पहुंचता। बहरहाल, अगर तीसरा मोर्चा बन जाता है और सत्ता में आने में सफल हो जाता है (जिसकी

जहां तक राहुल बाबा का सवाल है, वो चीख-चीख कर कह रहे हैं- हमने भूखे लोगों को भोजन का अधिकार दिया। दिया तो ठीक किया, पर सिर्फ़ अधिकार देने से क्या होगा। अच्छा तो ये होता कि अधिकार न देते, भोजन ही दे देते। भोजन तो गोदामों में बंद सड़ रहा है, सिर्फ़ अधिकार ले कर लोग उसे क्या चाटेंगे। लेकिन राहुल बाबा पूरे बाबा हैं।

संभावना नहीं के बराबर है) तो मुलायम प्रधानमंत्री बन पूरे देश में ‘महा गुंडाराज’ की स्थापना करने में दो मिनट की देर भी नहीं करेंगे।

देखना है, मायावती और ममता जैसी बांकुड़ियों की क्या भूमिका रहती है। ये तो हर्गिज तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं हो सकतीं। मुलायम से छत्तीस का आंकड़ा मायावती का, तो वामपंथियों से ममता का। वैसे भी, वामपंथियों का प्रभामंडल समाप्त हो चुका है। मीडिया में भी इनसे संबंधित ख़बरें नहीं के बराबर आ रही हैं। इनके एक नेता ने नोटों के बंडल पर सोने का अपना सपना पूरा किया तो वाम पार्टी को अपनी नैतिकता का ख़्याल करते हुए उसे पार्टी से बाहर करना पड़ा। इधर, नितीश कभी कांग्रेस की तरफ़ झुकते दिखाई पड़ते हैं तो तीसरा मोर्चा के निर्माण के लिये होने वाली बैठकों में भी शिरकत करते हैं।

बहरहाल, आम चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। दोनों तरफ़ से अभियान शुरू हो चुका है। नरेन्द्र मोदी पूरे देश में रैलियां कर रहे हैं। जबरदस्त भीड़ खींच रहे हैं। सिंह-गर्जना कर रहे हैं। उनके मुकाबले राहुल बाबा नौसिखिए और पिद्दी नज़र आते हैं। इस तरह चीख-चीख कर भाषण देते हैं राहुल बाबा कि समझ में ही नहीं आता, कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरे दिन अख़बारों से ही पता चलता है कि राहुल बाबा ने क्या कहा, क्या नहीं।

नरेन्द्र मोदी संघ के सधे हुए प्रचारक रहे हैं। लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। दंगों के मास्टर खिलाड़ी हैं। प्रधामंत्री बनने का इनके पास पहला और आख़िरी मौका है। हर तिकड़म और फ़रेब करेंगे। यूपी और एमपी में छोटे-मोटे दंगे हुए हैं। संघ परिवार कुछ और दंगों के आयोजन करवाये तो वोटों का ध्रुवीकरण तेज़ी से होगा-‘मतदान की फ़सल लहलहाएगी।’

वैसे, सिर्फ़ भाषणबाजी की बदौलत ही कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो इस देश में भाषण-वीरों की कोई कमी नहीं रही है। भाषण देकर लोगों की भावनाओं को भड़काने से आसान कुछ और है नहीं, पर यह शुरू-शुरू में होता है। भाषण सुन-सुन कर जनता के कान पक गए हैं। उसके अंदर अब ज्यादा कुछ भड़कता नहीं। अगर भड़कने लगे तो मोदी जैसों का पत्ता साफ़ होते देर भी न लगे।

मोदी मुसलमानों को अभयदान भी दे रहे। उनके कहने का लब्बोलुवाब है कि मुसलमानों को उनसे डरने की जरूरत नहीं। वो दंगा-फ्री राज कायम करेंगे। मंदिर भी बनाएंगे। जिन्होंने मस्जिद गिरायी है, उनका क्या करेंगे? इस पर मोदी खामोश रहते हैं।

चंद बरसों में ही मोदी देश के लोकतंत्रवादियों के बीच अपने हिटलरी तेवर को लेकर बदनाम हो चुके हैं। विदेशों तक इनकी कुख्याति फैल चुकी है। देश के बड़े-बड़े उद्योगपति इनके समर्थक हैं- टाटा से लेकर अंबानी तक। वैसे, अंबानी दिल्ली में कांग्रेस के दफ़्तर को अपना घर बताते हैं, पर इन पूंजीपतियों को पता है कि हिटलरी तेवर वाले मोदी के राज में उनकी लूट के क्षेत्र का विस्तार होगा। सत्ता में आते ही मोदी इन्हें खुली लूट का लाइसेंस जारी कर देंगे। इसके बाद अंबानी अपने बीबी के जन्म दिन पर 300 करोड़ रुपये उड़ाने की जगह बड़े मजे में एक हज़ार करोड़ रुपए उड़ा सकते हैं, इस ‘जनतंत्र’ में किसी को पूछने का ये हक़ ही नहीं होगा कि ये माजरा क्या है।

मोदी विकास की बात करते हैं। विकास का गुजरात मॉडल दिखाते हैं, गुजरात इस देश से अलग नहीं। वहां भी उतनी ही भूख है जितनी बिहार या ओडिशा में। पर झूठ मोदी का औजार है जैसे हिटलर के प्रचार मंत्री गोयेबल्स का था। देखना है, इस झूठ के दम पर मोदी कहां तक पहुंचते हैं।

जहां तक राहुल बाबा का सवाल है, वो चीख-चीख कर कह रहे हैं-हमने भूखे लोगों को भोजन का अधिकार दिया। दिया तो ठीक किया, पर सिर्फ़ अधिकार देने से क्या होगा। अच्छा तो ये होता कि अधिकार न देते, भोजन ही दे देते। भोजन तो गोदामों में बंद सड़ रहा है, सिर्फ़ अधिकार ले कर लोग उसे क्या चाटेंगे। लेकिन राहुल बाबा पूरे बाबा हैं। भाषण दे दिया किसी नौसिखुआ छात्र नेता की तरह, जल्दी ही थक गए, फ़िर कुर्ता पाजामा की जगह जींस-टी-शर्ट धारण किया और चल पड़े वाड्रा संग मौज मस्ती, धूम-धड़ाका, धमाल करने।

इसलिए, कांग्रेस की सरकार नहीं बननी और राहुल बाबा को प्रधानमंत्री नहीं बनना। जनता नेहरू-गांधी परिवार की चौथी-पांचवीं पीढी को झेलने के लिए तैयार नहीं। तो फ़िर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? राजनीतिक पंडित ये भी तय नहीं मानते। तो फिर ‘धरतीपुत्र’ मुलायम? नहीं नहीं, अनिश्चय की स्थिति है। इस बीच, नाच-तमाशा जारी है। कई सितारे आएंगे नाच दिखाने। बॉलीवुड सुंदरियां ठुमके लगायेंगी। जनतंत्र का मजा लीजिए।

प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सस्पेंस है। फ़िक्र मत कीजिए। कोई न कोई तो बन ही जाएगा। आपको फ़र्क क्या पड़ना है। शांत! प्रहसन जारी है। ■

तुर्की-ब-तुर्की

अरुण जेटली

“(उत्पीड़ित) महिला की निगरानी नहीं उसकी सुरक्षा कर रही थी गुजरात पुलिस”

हमारा कहना है-

- यह संभवतः दुनिया का अकेला मामला होगा जिसमें सुरक्षा, निगरानी के तौरतरीकों से की गई। जो महिला इस विवाद के केंद्र में हैं, उनके फ़ोन की टैपिंग की गयी; खुफ़िया तौर पर उन पर नज़र रखी गयी; पुलिस के जासूसों द्वारा उनका पीछा किया गया; वे कहां जाती हैं, किससे मिलती हैं, इन सब का रिकार्ड गृह मन्त्री अमितशाह की मार्फ़त मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी तक पहुंचाया जाता रहा। अगर इसी को सुरक्षा कहते हैं तो जासूसी किसे कहेंगे?

- जेटली जी आप एक जाने-माने वकील हैं। कहते हैं एक अच्छा वकील अपनी दलील से कानून और न्याय की दिशा बदल सकता है। आपने तो सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान दोनों की ही दशा बदल दी है। न आम आदमी आपके तर्क को समझ पा रहा है और न ही पेशेवर सुरक्षाकर्मी। फ़िर अगर निगरानी ही करनी थी तो उन संदिग्ध व्यक्तियों या संगठनों की करनी चाहिये थी जिनसे महिला को कथित खतरा था। यहां तो स्वयं महिला की ही जासूसी की गयी है, जिससे लगता है कि मोदी को स्वयं उस महिला से ही खतरा रहा होगा। इस बाबत तरह-तरह के कयास हैं। यौनिक उत्पीड़न के भी।

- अगर मोदी की गुजरात सरकार जासूसी को ही सुरक्षा का सबसे प्रभावी कवच मानती है तो स्वयं नरेन्द्र मोदी को भी ऐसी ही सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती? उनके साथ 108 एन एस जी कमांडों का दस्ता बड़ी-बड़ी रायफलें लिये क्यों दिखाई देता है? क्यों उनके लिये भाजपा द्वारा एस पी जी के सुरक्षा कवच की मांग की जाती है? इस विवाद में फंसे मोदी के लिये इससे निकलने के लिये यह सबसे आसान तरीका होगा कि वह अपनी एन एस जी सुरक्षा को छोड़कर ‘जेटली सुरक्षा’ को अपना लें।

- अब जेटली जी, आप इसे सुरक्षा का नाम दें या निगरानी का, पर साथ यह भी बता दें कि स्वयं मुख्यमंत्री/गृहमंत्री के सीधे आदेश से की जाने वाली फ़ोन टैपिंग में निर्धारित प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गयी? ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा राज्य के गृह सचिव से अनुमति लेनी होती है, जो इस मामले में नहीं ली गयी। आख़िर क्या था जिसे छिपाया जा रहा था? लगे हाथ इसका खुलासा भी क्या आपको नहीं करना चाहिये?

- और जेटली जी जब उस महिला के फोनों को टेप करने को आप सुरक्षा मान रहे हैं तो आपके फोन टेप करने वालों को फिर किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, वो भी तो आपकी सुरक्षा में ही लगे होंगे।

मरते बच्चे, बढ़ते अरबपति

हर साल 16 लाख बच्चों को निगल जाती है यह व्यवस्था

हमारा देश आज विश्व में बच्चों का सबसे बड़ा कत्लगाह हो गया है। 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 16 लाख बच्चे प्रत्येक वर्ष काल के गाल में समा जाते हैं। इनमें से 8 लाख बच्चे तो अपने जीवन का एक माह भी पूरा नहीं कर पाते। हमारे देश की ढाई करोड़ महिलायें गर्भधारण के दौरान और उसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती है, जिसके कारण नवजात शिशु मृत्यु दर साल दर साल बढ़ती जा रही है। विकास दर के मामले में विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, वहीं बच्चों की मौत के मामले में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। विकास के जिस रास्ते पर देश चल रहा है, वहां देश के नौनिहालों के लिये कोई जगह नहीं है। चिन्ता है तो बस अमीरों के भविष्य की।

हमारे देश में 5 करोड़ बच्चों का वजन अपनी उम्र के सामान्य बच्चों से कम है। सभी राज्यों में प्रति हज़ार 59 बच्चों की मौतें होती हैं। इनमें झारखण्ड और असम बच्चों की मौतों के मामले में सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में भी बच्चों की मृत्यु दर बद से बदतर है। उड़ीसा के कंधमाल में 145 प्रति हज़ार, श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में 142 प्रति हज़ार और पन्ना (मध्य प्रदेश) में 140 प्रति हज़ार बच्चे हर साल मरते हैं।

किसी भी समाज की बेहतरी का पैमाना वहां के बच्चों की स्थिति होती है। आखिर हमारे शासक वर्ग और मीडिया इन खबरों के प्रति इतने असंवेदनशील क्यों हैं? प्रति वर्ष 16 लाख बच्चों की अकाल मौत भी उनके मन मस्तिष्क में कोई हरकत क्यों नहीं पैदा कर पाती? मौत के शिकार ये बच्चे भारत की बहुसंख्यक मेहनतकश जनता के बच्चे हैं। देशी-विदेशी पूंजीपतियों का मुनाफ़ा बढ़ता रहे, उनकी अय्याशी चलती रहे इसके लिये हमारे शासक वर्ग कार्य कर रहे हैं और इसमें वे सफल भी हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे भले ही मरते रहें, अमीरों की खुशहाली में कोई कमी न आये।

-देश-विदेश